चिदम्बरम् जी के द्वारा जो बजट गांव, गरीब और किसानों के लिए प्रस्तुत किया गया है उससे प्रोत्साहित हो करके और बहुत आशा भरी नज़रों से मैं इस देश के लाखों किसानों का ज्वलंत सवाल है और हमारे वित्त मंत्री यहां मौजूद हैं मैं उस समस्या को यहां रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण हमारे वित्त मंत्री जी देंगे।

महोदया, पिछली सरकार ने सन् 1977 में घोषणा की थी कि 2 अक्तूबर 1986 से 2 अक्तूबर 1989 तक किसानों की फसल प्राकृतिक विपदाओं के कारण अगर लगातार दो वर्षों तक बर्बाद हो गई हो और स्थानीय पदाधिकारी द्वारा 50 परसेंट से अधिक की क्षति का प्रमाण-पत्र दिया गया हो तो व्यवसायिक बैंकों के द्वारा लिया गया ऋण 10 हजार तक मुआफ कर दिया जाएगा।

सरकार की इस घोषणा के तहत देश के बड़े बड़े किसान तो लाभान्वित अवश्य हुए, परन्तु लाखों छोटे किसान तकनीकी कारणों से इस लाभ से वंचित रह गए। माफी की अवधि में इन किसानों ने ऋण अदायगी नहीं की, फलस्वरूप मूलधन से अधिक आज ब्याज किसानों पर चढ़ गया है। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि किसानों की कुर्की, जब्ती की नौबत आ गई है और जो उनकी छोटी संपत्ति है, उनकी पठिया और खटिया है उसे भी बेचने को बाध्य हो रहा है।

उपसभापति महोदया, आज स्थिति ऐसी है कि छोटा किसान अगर अपनी सारी जमीन भी बेच दे तो भी व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिया गया ऋण वह चुकता नहीं कर सकता। अतः किसानों की इस गंभीर समस्या की ओर मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से और अपने माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि उक्त अवधि में किसानों के द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज को, मैं यह नहीं कहता कि ऋण माफ कर दिया जाए, लेकिन कम से कम उक्त अवधि में किसानों के द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज को माफ कर दिया जाए। इससे देश में आमदनी भी बढ़ेगी क्योंकि किसानों के पास जो करोड़ों रुपए बकाए हैं, उस ऋण को किसान सहर्ष भुगतान करने को तैयार हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या आज प्रशासन के सामने, राज्य सरकारों के सामने जो पड़ी हुई है, वह यह कि किसान पैसा दे नहीं सकता है और सरकार के लिए ऋण वसूलना बहुत जरूरी है। यह एक बहुत बड़ा सवाल किसानों के सामने भी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से ध्यान देते हुए माननीय वित्त मंत्री जी इस मामले में कुछ न कुछ इस देश के किसानों के लिए राहत की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Finance Minister is here and he has heard it. I am sure that he is going to take action.

## Alarming Situation in Hindustan Shipyard Visakbapatnam due to Withdrawal of orders for Ship Building

**डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद (आन्ध्र प्रदेश):** आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन और सरकार की दृष्टि हमारे राज्य की, खासकर हमारे विशाखापट्टणम महानगर की एक विशेष समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में चार बड़ी नौका निर्माण संस्थाए हैं। इनमें गार्डेन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कलकत्ता और मजगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई यह दोनों रक्षा संबंधी शिप निर्माण में लगे हुए हैं और कोचीन शिप यार्ड नौकाओं की मरम्मत में संलग्न है। देश और विदेश की नौकाओं का निर्माण करने वाला और विदेशी मुद्रा कमाने वाला एक मात्र शिप यार्ड आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम में स्थित "हिन्दुस्तान शिप यार्ड" रह गया है।

मैडम, इसका एक इतिहास है। इसकी आधारशिला स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद जी द्वारा रखी गई थी। इस यार्ड द्वारा निर्मित पहला पोत "जल ऊषा" का वर्ष 1949 में स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा जलावतरण किया गया था। इस यार्ड द्वारा अब तक एक सौ से अधिक जहाजों का निर्माण हुआ है और पन्द्रह सौ से अधिक जहाजों की मरम्मत की गई है। ऐसी संस्था अब बंद होने की सर्वनाश की कगार पर खड़ी रक्षा करने वाले की ओर ताक रही है।

मैडम, 1995 तक भारत सरकार द्वारा हिन्दुस्तान शिप यार्ड को 30 प्रतिशत की सबसिडी दी गई, परन्तु उस सबसिडी को बंद करने से हिन्दुस्तान शिप यार्ड को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सबसिडी रद्द करने से 6 नौकाओं और एक ट्रेडजर के निर्माण के जो आर्डर दिए गए, वे वापिस ले लिए गए हैं। इसके कारण वहां काम करने वाले 5000 मजदूर और उनके परिवार अपनी जीविका खो बैठे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं, खासकर माननीय वित्त मंत्री जी से, जो सभा में उपस्थित हैं, कि सरकार

सबसिडी को पुनः देकर हिन्दुस्तान शिप यार्ड की रक्षा करे।

एक और बात, मैडम, हिन्दुस्तान शिप यार्ड को "इन्वेस्टमेंट का पुर्नव्यर्स्थीकरण" का वायदा भारत सरकार आठ सालों से लगातार करती आई है! हाई पावर कमेटी और भूतल परिवहन मंत्रालय ने इसकी सिफारिशें भी की हैं। इसके पहले ऐसी सुविधा कोचीन शिप यार्ड को दी गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह विनती करना चाहता हूं कि "कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग" करके हिन्दुस्तान शिप यार्ड को बचाना चाहिए।

मैडम, एक छोटी सी बात और कि वहां 1992 में पे-रिवीजन हुआ, परन्तु अभी तक रिटायर्ड एम्पलाइज को भी एरियर्स नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार की दृष्टि इस ओर भी लाना चाहूंगा। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: There isi name written here. Dr. Y. Radhak-rishna Murty's name is already there. Have you asked to speak to associate on this?

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY (Andhra Pradesh): Yes, Madam. Madam, I would like to associate myself with what my hon. friend has stated. Vishakapatnam Shipyard is one of the best industries that Andhra Pradesh has got. As all the Members know Andhra Pradesh is very backward in the industrial arena. We have got very few industries and it is one industry where 5,000 workers have been employed and another 50,000 families are living in the ancillary. Now, this big industry is facing the danger of closure and one point which the industry requires from the Government of India is the capital restructuring which has pending for the last eight to ten years with the Government. The proposals were sent in 1980. Till 1980, the Hindustan Shipyard was making profits. From then onwards the trouble started because of some recession in the international market. So the profits turned into losses. And then the industry was facing unemployment. They requested for two things. One was capital restructuring and the second was increasing and rationalising the subsidy. The two requests were made by the industry and these two things were pending for eight years in the Government of India. Committees after committees were formed and reports after reports were dished out. But the result was, in 1993 an award was given not for capital restructuring but only for some sort of subsidy and about 9 per cent interest rate was given to the externr of 80 per cent of the cost of ship building. And interestingly, Madam, this was given only for a short period of two years and that two-year period had elapsed and the Government had given this and this also has elapsed along with this. So, now again, the situation has come to square one. So we would request the Government of India to go in for capital restructuring and also give a rational subsidy which the other countries have been giving for the shipbuilding industry. There are many countries which have been giving 40 to 60 per cent subsidy in the world including countries like UK, USA, Poland, China and Japan. All these countries have given 40-60 per cent subsidy. We request that, if the Government of India wants the shipyard to survive and the 5,000 workers to survive and the 15,000 ancillary industries to survive, then these two things have to be considered; the capital restructuring will have to be considered and given early consideration. Thank you, Madam.

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिम बंगाल): मैडम, यह जो मामला उठाया गया है, वित्त मंत्री जी भी हैं, वित्त मंत्री जी ने कल बजट में यह बात कही कि हमारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, हम बजट को उस तरफ दिशा दे रहे हैं लेकिन हमारे देश में दिक्कत यह है कि जो इन्सटाल्ड केपेसिटी है, उसका हम सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। विश्व के हर देश में, जो भी शिपिंग में आगे है, वे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को सब्सिडी देते हैं। विदआउट सब्सिडी शिपिंग बिल्डिंग इंडसरी वायबल नहीं हो सकती। 80 से, 80 से पहले जो रिसेशन थी वर्ल्ड वाइड, उसके कारण इन सब कम्पनियों को दिक्कत आई, लेकिन उसी समय से हम नई दिशा में हमारी अर्थ-नीति को ले गए, जिसका नतीजा आज यह है कि शिप-यार्ड में हमें बस की बाडी बनानी पड़ रही है, रेल का गार्डर

बनाना पड़ रहा है और दूसरी तरफ हम चीख रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करते हैं। हम जहाज बनाना चाहते हैं, जहाज हमको विदेश से खरीदना पड़ रहा है। वर्ल्ड वाइड रिसेशन खत्म हो गया है, शिपिंग इंडस्ट्री में एक नया बूम पैदा हुआ है और जब बूम पैदा हुआ है, चाहे वह शिपिंग कारपोरेशन हो, चाहे प्राइवेट शिपिंग कम्पनीज़ हो, हम विदेश से जहाज खरीद रहे हैं

†[شری محمد سلیم (مغربی بنگال): میڈم -
یہ جو معاملہ اٹھایا گیا ہے - وت منتری جی
بھی ہیں وت منتری جی نے کل بحث میں
یہ بات کہی کہ ہمارا جو "انفراسٹرکچر" ہے -
ہم بحث کو اس طرف دشا دے رہے ہیں اور
ہمارے دیش میں دقت یہ ہے کہ جو انسٹالڈ
کیپیسٹی ہے - اسکا ہم صحیح طریقے سے "یو
ٹیلائزیشن" نہیں کر پا رہے ہیں - دنیا کے ہر
ملک میں جو بھی "شپنگ" میں آگے ہیں -
وہ شپنگ بلڈنگ انڈسٹری کو سبسڈی
دیتے ہیں - ودآؤٹ سبسڈی شپنگ بلڈنگ
انڈسٹری وائیبل نہیں ہو سکتی - ۸۰ سے
پہلے جو "ریسیشن" تھی ورلڈ وائڈ اسکی وجہ
سے ان سب کمپنیوں کو دقت آئی - لیکن
اسی وقت سے ہم نئی دشا میں اپنی "ارتھ
نیتی" کو لے گئے - جسکا نتیجہ آج یہ ہے کہ
شپ یارڈ میں ہمیں بس کی باڈی بنانی
پڑ رہی ہے "سیل" کا گارڈر بنانا پڑ رہا ہے
اور دوسری طرف ہم چیخ رہے ہیں کہ ہمارے
پاس پیسے نہیں ہیں ہم انفراسٹرکچر کو ڈیولپ
نہیں کرتے ہیں ہم جہاز بنانا چاہتے ہیں - جہاز
ہم کو ودیش سے خریدنا پڑ رہا ہے - ورلڈ
وائڈ ریسیشن ختم ہو گیا ہے شپنگ انڈسٹری
میں ایک نیا بوم پیدا ہوا ہے - اور جب بوم]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is this an association or a speech?

SHRI MD. SALIM: I will conclude, Madam. I will conclud it. *(Interruptions)*

शिपिंग के बारे में यह है कि हमारे देश की अर्थ-नीति ...(व्यवधान)...

[پیدا ہوا ہے - چاہے وہ "شپنگ کارپوریشن
ہو - چاہے پرائیویٹ شپنگ کمپنیز ہوں -
ہم ودیش سے جہاز خرید رہے ہیں...]

**श्री मोहम्मद सलीम**: मैडम, आप बंबई से आती है ...(व्यवधान)

[شپنگ کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے
دیش کی "ارتھ نیتی"... "مداخلت"...]

**उपसभापति**: मैं हिन्दुस्तान में रहती हूं।

**श्री मोहम्मद सलीम**: मैडम, शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वैस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया- शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए और यह फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। वे बंबई में बिल्डिंग बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं लेकिन शिपिंग में वह पैसा नहीं जा रहा है। तो क्या मंत्री जी शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वैस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को वित्त मंत्रालय से मुक्त करके सरफेस ट्रांसपोर्ट के साथ जोड़ देंगे ताकि जो पैसा वे इक्ट्ठा कर रहे हैं, वह हमारे देश के शिपिंग उद्योग को बढ़ावा देने के काम में आए? मैडम, हमारा जो कार्गो है, वह विदेश की शिपिंग कंपनियां ले जा रही हैं क्योंकि अपने देश के कार्गो की परिवहन के लिए हमारे पास अपना शिपयार्ड नहीं है।

†[شری محمد سلیم: میڈم - آپ بمبئی سے آتی
ہیں... "مداخلت"...]

†Transliteration in Arabic Script.

†[شری محمد سلیم: میڈم - "شپنگ ٹریڈنگ انوسٹمنٹ کارپوریشن آف انڈیا" بنایا گیا - شپنگ انڈسٹری کو بڑھاوا دینے کیلئے اور یہ فائننس منسٹری کے تحت ہے - وہ بمبئی میں بلڈنگ بنا رہے ہیں - زمین خرید رہے ہیں - لیکن شپنگ میں وہ پیسہ نہیں جا رہا ہے - تو کیا منتری جی شپنگ ٹریڈنگ انوسٹمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کو وت منترالیہ سے الگ کر کے "سرفیس ٹرانسپورٹ" کے ساتھ جوڑ دینگے تاکہ جو پیسہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں وہ ہمارے دیش کے شپنگ ادیوگ کو بڑھاوا دینے کے کام میں آئے - میڈم - ہمارا جو کارگو ہے وہ ودیش کی شپنگ کمپنیاں لے جا رہی ہیں کیونکہ اپنے دیش کے "کارگو" کو نکالنے کیلئے ہمارے پاس اتنا "شپ یارڈ" نہیں ہے -]

SHRI MD. SALIM: We also have'a shipyard Goa, Madam.

SHRI JOHN F. FERNANDES (GOA): Madam, it is controlled by the trade unions of the Left groups. It is reported that building ships abroad is much cheaper than in our country. What we have to see is that the work culture in this country improves. I think if the Leftist trade union people control all the workers, I think we will make profit and this industry will not be in recession. The best example is the shipyard in Cochin. It is now going in the red because it is controlled by the trade unions which belong to Leftists. That is what I want to say, Madam.

†[ ] Transliteration in Arabic Script

**Need to take adequate anrt Effecuve Measures to check for Pollution in the Country particularly in Metropolitan Cities**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Iq-bal Singh.

**श्री इकबाल सिंह** (पंजाब): महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महानगरों में बढ़ते पोल्यूशन को रोकने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैडम, इस मशीनी तथा तकनीकी युग में एयर तथा साउंड पोल्यूशन ने देश के नगरों और विशेषकर महानगरों जैसे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर आदि में भयंकर स्थिति पैदा कर दी है। इन महानगरों में एयर पोल्यूशन को रोकने की बहुत आवश्यकता है।

मैडम, इन महानगरों में डीज़ल पेट्रोल से चलने वाले वाहन जैसे मोटरसाईकिल, ट्रक, करें, थ्री-व्हीलर, टैक्सियां आदि रात-दिन सड़कों पर दौड़ते हैं। इन वाहनों से कार्बन-डाई-आक्साइड, सल्फेट्स, एसिड्ज़ तथा अन्य हानिकारक पदार्थ निकलते हैं जो हवा में घुल जाते हैं और वायु को प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रदूषण से दमा, टी॰बी॰, कैंसर, खांसी-जुकाम आदि बीमारियां हो जाती हैं। इस प्रदूषण से त्वचा तथा नेत्र काफी प्रभावित होते हैं। इसलिए इन महानगरों में पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार को विशेष उपाय करने चाहिए ताकि लोगों को इन खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सके।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश के नगरों और महानगरों में जो पोल्यूशन निरंतर बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए ठोस व प्रभावी कदम उठाए। सरकार ने जो पोल्यूशन कंट्रोल नार्म्स बनाए हैं, उनका पालन करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। देश के नगरों और महानगरों में इन पोल्यूशन पैदा करने वाले उद्योगों को उस स्थान से निकालकर दूसरे स्थानों पर स्थापित किया जाए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 141 उद्योगों को पोल्यूटेड घोषित किया है। उन्हें उस स्थान से हटाने के आदेश दिए जाएं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंप्लीमेंटेशन किया जाए।

महोदया, इसके अलावा सरकार को ऐसी नेशनल पालिसी बनानी चाहिए जिससे महानगरों में एकत्रित कूड़ा-करकट और खतरनाक पदार्थों को बेहतर ढंग से नष्ट किया जा सके। इंडस्ट्री से निकले कूड़ा-करकट को नष्ट करने हेतु नार्म्स बनाए जाएं, स्वच्छता पर विशेष बल दिया जाए और देश में ऐनवायरनमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग आदि को बढ़ावा दिया जाए तथा वातावरण को स्वच्छ करने हेतु देश की जनता में अवेयरनैस लाई जाए।